उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

देवभूमि उद्यमिता योजना

उत्तराखण्ड के शैक्षणिक परिसरों में उद्यमिता को बढ़ावा

कार्यान्वयन संस्था:

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान

अहमदाबाद

देवभूमि उद्यमिता योजना

भारत के 27वें राज्य के रुप में उत्तराखण्ड की स्थापना 9 नवंबर, 2000 को हुई। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति विविधता से भरी है। बर्फ से आच्छादित हिमालयी चोटियां, घाटियां, हिमनदियां (ग्लेशियर्स), झीलें और धूल भरे मैदान इसे देश का गौरवशाली राज्य बनाते हैं। प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों और मंदिरों की पवित्र भूमि होने के नाते उत्तराखण्ड न केवल भारत बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं हथकरघा, पयर्टन और वानिकी के क्षेत्र में यह प्रदेश प्रचुर क्षमतावान है। यहां के अनुकूल उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे के विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं।

भारत का आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश इस समय अनुकूल स्थिति में है। इस समय देश को ऐसी संरचना विकसित करने की जरुरत है, जिसमें यहां की युवा जनसंख्या को लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सके। ऐसे में उद्यमिता को विकास के एकीकृत मॉडल के रुप में अंगीकार किया जा सकता है। उत्तराखण्ड, जिसकी साक्षरता दर 79.63 प्रतिशत है, उसे युवाओं में शिक्षा, दक्षता और कुशलता विकसित करने का ऐसा सुअवसर प्राप्त है, उसके माध्यम से प्रदेश उद्यम के नये उपक्रमों को आसानी से पैदा कर सकता है। इसके लिए उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड में पर्यावरणीय कारक, राजनैतिक परिवेश, कानूनी ढांचा, बाजार की स्थिति, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य सभी समन्वय में हैं, जो सतत समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करते हैं। विकास के उपकरण के रुप में उद्यमिता ने यह सिद्ध कर दिया है कि समावेशी समृद्धि, सतत विकास और संसाधनों के अधिकतम दोहन में वह पूर्णतः सक्षम है। अपने अनुभवों के आधार पर भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) कौशल आधारित समृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

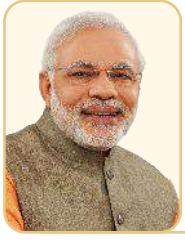

उत्तराखण्ड का सामर्थ्य अदभुत और अतुलनीय है, इसलिए मेरा विश्वास कि ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होने वाला है। यहाँ हर क्षेत्र में विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं जो उत्तराखण्ड को सशक्त बनाने में सहायता प्रदान करेंगी।

श्री नरेन्द्र मोदी जी
मा. प्रधानमंत्री, भारत सरकार

सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की संकल्पना के अनुरूप देवभूमि उद्यमिता योजना ने युवा उद्यमिता के माध्यम से नए उद्यम और सशक्त तथा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्री पुष्कर सिंह धामी
मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार

समर्थ और सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण की दिशा में देवभूमि उद्यमिता योजना, उच्च शिक्षा विभाग की महत्त्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार के वातावरण का सृजन करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में योजना राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। मैं इस योजना की सफलता की कामना करता हूँ, और योजना से जुड़े सभी छात्रों, शिक्षकों, प्रतिभागियों और टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ।

डॉ धन सिंह रावत
मा. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री शैलेश बगौली, ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ल से चर्चा करते हुए।

देवभूमि उद्यमिता योजना

दृष्टिकोण

शैक्षिक परिसरों, ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित व हाशिये पर पड़े सीमांत लोगों में समग्रता एवं कुशल रणनीति के माध्यम से उद्यमशीलता का विकास तथा स्टार्ट अप निर्माण के मिशन को मजबूत करना।

उद्देश्य

शैक्षिक संस्थानों के अंदर और बाहर तथा उत्कृष्टता के केंद्रों में नौजवान पुरुषों व महिलाओं को उद्यमिता और उसके लाभ के बारे बताना ही योजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन्हें प्रेरित करना कि स्वरोजगार और उद्यमिता को वे अपने करियर का बेहतर विकल्प समझें। यह कार्यक्रम युवकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उनकी गतिशीलता के प्रति समझ भी विकसित करेगा। इस कार्यक्रम के लाभ नये उद्यम निर्माण, रोजगार सृजन, समावेशी और संतुलित विकास, आर्थिक वृद्धि के मानकों और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में राज्य के महत्वपूर्ण योगदान में दिखाई देंगे।

कार्ययोजना

नये उद्यम लगाकर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम युवा उद्यमियों को पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान युवाओं में उद्यमशीलता की भावना पैदा करेगा, साफ्ट स्किल (व्यवहारिक कौशल) और अवसर पहचानने की कुशलता विकसित करेगा। तत्पश्चात् संस्थान व्यवसाय योजना के निरुपण और लघु व्यवसाय के प्रबंधन में सहयोग करेगा तथा व्यवसायिक मध्यस्थता की श्रृंखला के माध्यम से नये उद्यमों का शुभारम्भ करायेगा।

इसके साथ साथ भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से उत्तराखण्ड के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में देवभूमि उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। उद्यमिता केन्द्र का उद्देश्य संस्थानों में राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट अप नीति 2019, क्षेत्रीय उद्यमी पारिस्थिति की तंत्र का विकास और आईपी का व्यावसायीकरण करना है। देवभूमि उद्यमिता केंद्र उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के मार्गदर्शन में एकल मंच का उपयोग करके उपरोक्त गतिविधियों को लागू करने और निगरानी करने के लिए एक व्यवस्थित संरचना प्रदान करता है। प्रत्येक केंद्र की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित हैं और राज्य स्तर पर केंद्र की रैंकिंग भी योजनाबद्ध है।

7 दिसंबर, 2022: उत्तराखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ईडीआईआई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और सह–अध्यक्षता राज्य के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने किया। प्रदेश के सभी कुलपतियों, सम्मानित सचिवों, निदेशकों, प्रधानाचार्यों और प्रोफेसर्स ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की।

कार्ययोजना

- संस्थान स्तर पर व्यवसाय योजना निर्माण के लिए बूट कैंप्स
- कुलपतियों, प्रधानाचार्यों, प्रमुख शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला
- स्टार्ट अप उद्यमिता फैकल्टी मार्गदर्शक विकास कार्यक्रम
- उभरते स्टार्ट अप अवसरों पर प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स
- मेगा स्टार्ट अप इवेंट और छात्र स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग
- उद्यमिता में 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता के केंद्र)
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत युवाओं के लिए देवभूमि उद्यमिता योजना
- स्टार्ट अप पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर गतिविधियां
- एनईपी 2020 के अनुसार व्यवसायिक और उद्यमिता के पाठ्यक्रम

अधिक जानकारी के लिये क्यूआर कोड स्कैन करें

योजना के विशिष्ट उद्देश्य –

- कुलपतियों, प्रधानाचार्यों और सरकारी कर्मियों को संवेदनशील बनाना तथा उद्यमिता एवं नई शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाना।
- उद्यमिता संबंधी शोध कार्यों का संचालन और ज्ञान उत्पाद (पुस्तक, पत्रिका आदि) का विकास करना।
- बूट कैंप के माध्यम से छात्रों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना।
- पर्यटन सेक्टर को विकास के प्रमुख चालक के रुप में बढ़ावा देना और इस सेक्टर से उद्यमियों को सहायता पहुंचाना।
- उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता के केंद्र) स्थापित करना।
- राज्य से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की तलाश करना और उच्चस्थ सरकारी कार्यालयों व कारपोरेट सेक्टर को राज्य से जोड़कर विकास के कार्यक्रम चलाना।
- मेगा स्टार्ट अप इवेंट, एमएसएमई और स्टार्ट अप प्रदर्शनियां और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंसेज के आयोजन करना।

लक्ष्य

शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के विद्यार्थी

आजीविका के अवसरों की तलाश में लगे युवा

हाशिये पर पड़े सीमांत और निःशक्त यानी पिछड़े वर्ग के युवक युवती

संभाव्य क्षेत्र

कृषि और वन उपज

प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा

निर्माण इकाईयां

उत्पादन सेवाएं

कृषि – खाद्य प्रसंस्करण

सांस्कृतिक प्रबंध

रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध

देहरादून में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से, आयोजित परामर्शदात्री कार्यशाला में, डॉ. सुनील शुक्ला,

डॉ. धन सिंह रावत,
माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,
उत्तराखण्ड
के साथ बातचीत

अंगोरा ऊन

आयुष

सुगंधित तेल

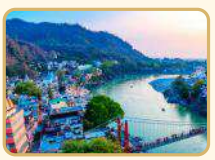

पर्यटन

इंटरनेट ऑफ थिंग्स

ड्रोन तकनीकी

सौर ऊर्जा

महानिदेशक, ईडीआईआई और ईडीआईआई के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों, संबंधित हितधारकों के साथ।

1 संस्थान स्तर पर व्यवसाय योजना निर्माण के लिए बूट कैंप्स

छात्रों को उद्यमिता में करियर और स्टार्टअप के अवसर के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थान अपने कालेज कैंपस में स्टार्टअप–उद्यमिता पर दो दिवसीय बूट कैंप आयोजित करेंगे। इस कैंप में छात्रों को एक बिजनेस आइडिया को स्वीकार करने और उस पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस डोमेन (कार्य क्षेत्र) के मुख्य बिंदुओं में सम्मिलित होंगे–

- छात्र व्यवसाय योजना निर्माण और प्रस्तुतीकरण
- व्यवसाय योजना का परिष्करण और मूल्यांकन

(40 बूट कैंप्स आयोजित कर लगभग 10,000 छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा)

2 कुलपतियों, प्रधानाचार्यों, प्रमुख शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला

'देवभूमि उद्यमिता योजना' पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षाविदों को योजना के उद्देश्यों के प्रति जागरुक करेगी। इस कार्यशाला में नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के संदर्भ में योजना की प्रासंगिकता को स्थापित करने के लिए विचार–विमर्श और मंथन के अतिरिक्त मध्यस्थता की आवश्यकता को भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही परिणामोन्मुख गतिविधियों के माध्यम से 'स्टार्टअप इंडिया स्टेट रैंकिंग' में प्रदेश की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में चिंतन होगा।

– उत्तराखंड के शैक्षिक परिसर अनुकूल उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारम्भ कर देंगे, जिससे 'स्टार्टअप इंडिया स्टेट रैंकिंग' में राज्य के प्रदर्शन में सुधार आएगा।
– नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन पूरे प्रदेश में किया जाएगा।

3 स्टार्टअप उद्यमिता फैकल्टी मार्गदर्शक विकास कार्यक्रम

प्रत्येक वर्ष उभरते हुए उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने और मार्गदर्शन के लिए प्रदेश के 13 जनपदों, 35 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 90 फैकल्टी सदस्यों के एक संवर्ग को चुन कर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में व्यवसायिक विचार, अवसर भांपने की क्षमता, सहयोग तंत्र और उद्यमिता के कानूनी पहलू, वित्त पोषण एवं अन्य सहायता, स्टार्टअप प्रबंधन, शिक्षण प्रक्रिया और उसके मॉडल्स, स्टार्टअप इनक्यूवेशन प्रक्रिया, इनक्यूवेशन केंद्र के परिचालन और प्रबंधन, आइडिया जनरेशन (विचार निर्माण) और शिक्षण रणनीति के विषय शामिल होंगे।

– क्षेत्रवार और विषय के अनुसार अगले पांच वर्ष में 350 मेंटर्स (मार्गदर्शकों) का समूह तैयार किया जाएगा।
– क्षेत्रवार स्टार्टअप के अवसरों की पहचान करके उनका डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।

4 उभरते स्टार्टअप अवसरों पर प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स

डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से उभरते स्टार्ट अप्स और उद्यमिता के अवसरों की तलाश की जाएगी। प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स विकसित किए जाएंगे और उन्हें विभिन्न संस्थानों और आकांक्षी उद्यमियों के साथ साझा किया जाएगा।

- 100 प्रोफाइल्स हर साल विकसित किये जायेंगे।
- अगले पाँच वर्षो में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों पर लगभग 350 प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स तैयार किये जायेंगे।

5 मेगा स्टार्टअप इवेंट और छात्र स्टार्ट अप्स को सीड फंडिंग

इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय उद्यमियों, निवेशकों का प्रस्तुतिकरण और छात्र स्टार्ट अप्स को सीड फंड (बीज निधिं) के वितरण शामिल होंगे।

राज्य स्तरीय आयोजन उन चयनित स्टार्ट अप्स के लिए होगा, जिन्होंने अपना बिजनेस प्लान प्रस्तुत कर दिया है। उन्हें अपने बिजनेस माडल्स और प्लान्स के प्रदर्शन के लिए इस आयोजन में आमंत्रित किया जाएगा। मौजूदा उद्यमियों और स्टार्ट अप्स के बीच आपसी सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

–निवेशक प्रस्तुतिकरण में निवेशक अपनी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखण्ड में उद्यम निधि स्थापित करने के लिए अवसरों की तलाश हेतु उद्यम वित्त कंपनियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।

–छात्र स्टार्ट अप्स को सीड फंड (बीज निधिं) वितरण कार्यक्रम में चयनित स्टार्ट अप्स को ही सहयोग प्रदान किए जाएंगे। इन स्टार्टअप्स को अपने उपक्रम प्रारम्भ करने का परामर्श भी दिया जायेगा।

यह सम्पूर्ण गतिविधि स्टार्ट अप के बारे में समझ को बढ़ावा देगी, संभावित उद्यमियों को प्रेरित करेगी और अपनी रुचि के स्टार्टअप खोजने के लिए प्रत्यक्ष निवेशकों को आकर्षित करेगी।

देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत आयोजित फैकल्टी मेंटर विकास कार्यक्रम के प्रतिभागी डॉ. सुनील शुक्ला, महानिदेशक, ईडीआईआई एवं कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ फैकल्टी – डॉ. अमितकुमार द्विवेदी और डॉ. अंजनी कुमार, के साथ

डॉ. सुनील शुक्ला, महानिदेशक, ईडीआईआई, देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत फैकल्टी मेंटर विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए। यह कार्यक्रम ईडीआईआई परिसर में आयोजित किया गया था।

6 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और सहयोग

ईडीआईआई राज्य के 20 अग्रणी संस्थानों की पहचान करेगी। उनमें किसी विशेष क्षेत्र या विषय में विशिष्टता प्रदान कर उन्हें उत्कृष्टता के केंद्र के रुप में विकसित किया जाएगा। ऐसे संस्थान जो आयुष, हर्बल दवा, आर्गेनिक खेती, पर्यटन, कृषि–खाद्य प्रसंस्करण, विरासत प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक्स और संचार, महिला उद्यमिता, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टीफिसियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका चयन करके उन्हें स्टार्ट अप्स और एमएसएमई उद्यमियों के सहयोग हेतु तैयार किया जाएगा।

शैक्षणिक ढ़ांचे से बाहर के युवकों को भी चयन प्रक्रिया से गुजरने और चयनित प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

7 उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत युवाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम

देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत राज्य भर में दो–दो सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उद्यम स्थापित करने के लिए चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और सलाह दी जाएगी। उभरते उद्यमों को एक वर्ष के लिए मेंटरिंग किया जाएगा। 18 से 45 वर्ष के बीच के लाभार्थियों का चयन परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। उन्हें व्यवसाय स्थापित करने और प्रबंधित करने, वित्तीय साक्षरता, परिचालन, नेटवर्किंग और विपणन आदि के कई पहलुओं पर जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

–लगभग 3000 युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।
–पाँच वर्ष में करीब 15000 युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे, जो कम से कम 9000 उद्यम स्थापित करेंगे और 36000 रोजगार का सृजन करेंगे।

8 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण पर जोर

अधिक से अधिक लोगों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु 'स्टार्ट अप विजन' दस्तावेज और एक काफी टेबल बुक विकसित और प्रसारित की जाएगी।

इनक्यूबेटर प्रबंधक विकास कार्यक्रम

ये राज्य स्तरीय इनक्यूबेटर प्रबंधक विकास कार्यक्रम परिसरों से उभरते स्टार्ट अप की खोज करने, राज्य के भीतर और बाहर दोनों से एक व्यापार सलाहकारों का पूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

9 नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार व्यवसायिक और उद्यमिता के पाठ्यक्रम

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार ईडीआईआई व्यावसायिक विषयों और उद्यमिता पर एप्लिकेशन उन्मुख अल्पकालिक पाठ्यक्रम विकसित करेगा। विधिवत अनुमोदित पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में डिजाइन और प्रस्तुत किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि सकारात्मक परिणाम पैदा करने के लिए शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक सीख की ओर बढ़ना चाहिए। यह रचनात्मकता, नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता, टीम वर्क, संचार कौशल, सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम के गहन अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का प्रचार करती है। इसे देखते हुए, उद्यमिता शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में, विशेषकर उच्च शिक्षण संस्थानों में, अधिक समग्र तरीके से एकीकृत करने की आवश्यकता है।

नीतिगत ढांचे का विकास

किसी समस्या की पहचान करने और नीतिगत ढांचे के माध्यम से उसका समाधान करने में कई कारक शामिल होते हैं। ईडीआईआई निरंतर आधार पर चुनौतियों पर शोध, विश्लेषण और समझ विकसित करेगा और नीति निर्माण, निर्देशों, विनियमों, संसाधनों के प्रावधान और सहयोग तथा जुड़ाव के माध्यम से हितधारकों की भागीदारी से इसका समाधान करेगा।

अन्य विकासात्मक पहल

- कला एवं शिल्प और पर्यटन आधारित उद्यमिता विकास परियोजनाएं
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए उद्यमिता और आजीविका पहल
- महिला उद्यमिता विकास परियोजनाएं
- स्कूल उद्यमिता कार्यक्रम
- दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने हेतु क्षेत्र के उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वालों, प्रशासकों और उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग करना

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के बारे में

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद की स्थापना 1983 में शीर्ष वित्तीय संस्थानों – आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से एक स्वायत्त और गैर–लाभकारी संस्थान के रूप में की गई थी। गुजरात सरकार ने तेईस एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जिस पर ईडीआईआई का भव्य और विशाल परिसर खड़ा है। ईडीआईआई को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।

संस्थान को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे (एनआईआरएफ), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवाचार श्रेणी के तहत 11–50 के बैंड में भी स्थान दिया गया है और गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उद्यमिता प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास, नवाचार और संस्थागत निर्माण में ईडीआईआई एक राष्ट्रीय संसाधन संस्थान की भूमिका अपनाने के लिए आगे बढ़ा है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और रवांडा में उद्यमिता विकास केंद्रों की स्थापना के साथ ईडीआईआई का विकास मॉडल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक हो गया है।

स्टार्ट अप और इनोवेशन पर जोर देने के अनुरूप, ईडीआईआई ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के सहयोग से, वर्ष 2016 में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, ब्त।कस्म् – सेंटर फॉर एडवांसिंग एंड लॉन्चिंग एंटरप्राइजेज की मेजबानी की। ईडीआईआई ने उद्यमिता को समझने के तरीके में सफलतापूर्वक बदलाव लाया है। संस्थान ने नवीन मॉडलों के माध्यम से और नए युग के संभावित उद्यमियों, अल्पसंख्यकों और वंचितों, मौजूदा उद्यमियों, इनक्यूवेशन केंद्र, पेशेवरों, नीति निर्माता और उद्यम पूंजीपतियों जैसे हितधारकों के बीच रचनात्मक मध्यस्थता करके विभिन्न खंडों और क्षेत्रों में उद्यमशीलता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता अर्जित की है।

संस्थान अपने 7 क्षेत्रीय कार्यालयों और अखिल भारतीय शाखा कार्यालयों के माध्यम से नीति वकालत, ज्ञान और अनुसंधान, उद्यमिता शिक्षा, परियोजनाओं (सरकारी और कॉर्पोरेट) व्यवसाय विकास सेवाओं और राष्ट्रीय आउटरीच तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के तहत विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं आयोजित करता है।

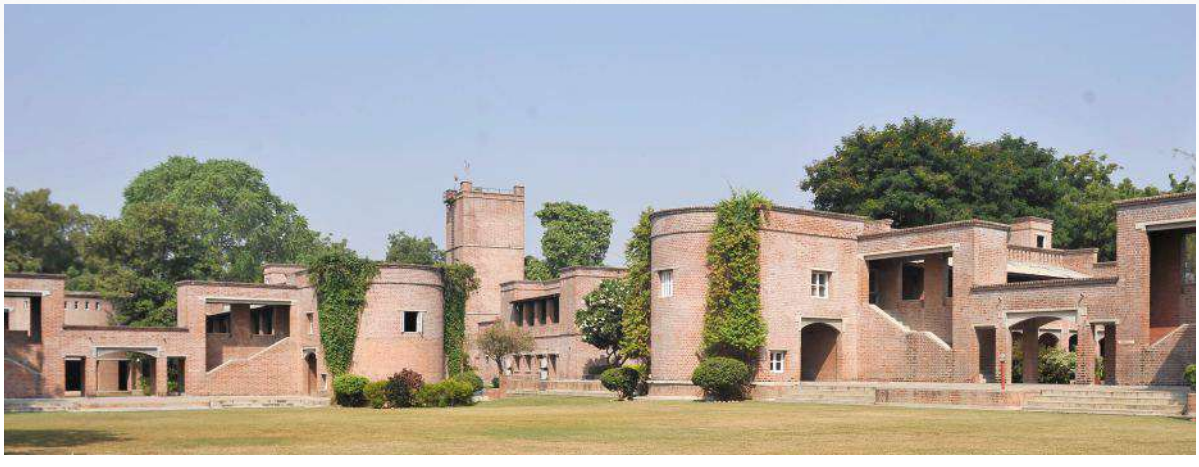

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई)
भाट, जिला–गांधीनगर – 382 428, गुजरात
फ़ोन 079- 6910 4900 / 6910 4999 ई–मेल info@ediindia.org
वेब www.ediindia.org/www.ediindia.ac.in